भारतीय खेल प्राधिकरण में अवर श्रेणी लिपिकों का नियमित किया जाना

66. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** 29 मार्च, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3344 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 32 अवर श्रेणी लिपिकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को नियमित किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन 36 अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाएं नियमित कर दी हैं जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे। इन 32 तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों का नियमन रिक्तियों की उपलब्धता अथवा अधिक नियमित पदों के सृजन पर निर्भर करेगा।

पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों का बंद किया जाना

67. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक उद्योगों को बंद करने का विचार रखती है; यदि हां तो देश में और विशेष रूप से राजस्थान में कौन-कौन से स्थानों पर ऐसे उद्योग स्थित हैं तथा इन्हें कब तक बंद कर दिया जायेगा;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में कोटा में तेजाबी वर्षा होने की जानकारी है तथा क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि वहां पर अत्यधिक उद्योगों के होने तथा तापविद्युत केन्द्रों के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है;

(ग) कोटा में पर्यावरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है तथा वहां उद्योगों के संबंध में भावी नीति क्या होगी; और

(घ) देश में तथा राजस्थान में पर्यावरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। सरकार ने देश में प्रदूषक उद्योगों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई आरम्भ कर रखी है। राजस्थान में थे उद्योग पाली और उदयपुर में स्थित हैं। पाली में चार यूनिटें और उदयपुर में दो यूनिटें पहले ही बंद कर दी गई हैं।

(ख) भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्थान में अम्ल वर्षा की समस्या नहीं है। कोटा में दो प्रमुख प्रदूषक यूनिटों, कोटा तापविद्युत केन्द्र और मैसर्स श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कैल्सियम कार्बाइड व सीमेंट संयंत्र, ने समुचित नियंत्रण उपकरण लगाकर प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं।

(ग) कोटा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए है। उद्योगों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि बहिस्राव एवं उत्सर्जन की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

(घ) 31 विशिष्ट उद्योगों के लिए बहिस्राव व उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। जल एवं वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। उद्योगों को विहित मानकों के अनुरूप समुचित शोधन प्रणाली लगाने का निदेश दिया गया है। दोषी यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

देश में वनों का विनाश

68. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल कितने क्षेत्र में वन हैं तथा राजस्थान के कितने क्षेत्र में वन हैं; सरकार द्वारा वनों के विनाश विशेष रूप से वन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वनों का विनाश रोके जाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक वानिकी पर कितनी धनराशि व्यय की है और इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई और क्या वास्तव में कोई पेड़ लगाये गये हैं और क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में खर्च की गई धनराशि की कोई लेखा परीक्षा की गई है; यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में सामाजिक वानिकी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले और गबन का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 75.14 मिलियन हेक्टेयर है। तथापि, भारतीय वनसर्वेक्षण ने 64.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की रिपोर्ट दी है। राजस्थान में 3.16 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। वन विनाश को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय अनुपत्र-1 के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक देश में सामाजिक वानिकी पर 1524.5 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इस अवधि के दौरान 5.656 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं।

(ग) राजस्थान में 1984-85 से 1988-89 तक सामाजिक वानिकी पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि एवं उस अवधि में वन लगाए गए क्षेत्र का विवरण अनुपत्र-2 में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में खर्च की गई धनराशि की लेखा परीक्षा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राजस्थान में सामाजिक वानिकी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले और गबन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

अनुपत्र–1

वन विनाश को रोकने के लिए किए गए उपाय

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को 1988 के संशोधनों द्वारा और अधिक कठोर बनाया गया है।

(2) राज्य वन सुरक्षा कार्मिकों की शक्ति को बढ़ाना।

(3) वनों की सुरक्षा हेतु कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों